कैसे बचे पानी

नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 02.07.2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया के सामने मंडरा रहे एक भयानक संकट की ओर ध्यान दिलाया है। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने जल संकट पर चिंता जाहिर की और कहा कि भारत में बारिश के पानी का संचय करने की कोई व्यवस्था न होने के कारण बहुत ज्यादा पानी बर्बाद हो जाता है। उन्होंने पानी के संरक्षण के लिए तीन अहम सुझाव दिए, एक तो यह कि इसके लिए जन आंदोलन की शुरुआत हो, दूसरे जल संरक्षण के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, तीसरा यह कि जल संरक्षण से जुड़ी सभी जानकारियां शेयर की जाएं। इसके लिए काम करने वाले लोगों से जो जानकारी मिले, उसे हैशटैग जनशक्ति फॉर जलशक्ति के साथ साझा किया जाए ताकि उसका एक डाटाबेस बनाया जा सके। भारत में जल संकट हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा है। चीन ने तो 1500 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का आंकड़ा आते ही वॉटर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था जबकि हमारे यहां जल उपलब्धता इससे नीचे जा चुकने के बाद भी हम इत्मीनान से हैं। 20 जून को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 27.265 अरब घन मीटर पानी बचा था, जो इनकी कुल संग्रहण क्षमता का मात्र 17 प्रतिशत है। पिछले दिनों चेन्नै के जल संकट की खबर आई। वहां इसी सप्ताह चार जलाशय सूख गए और अब बहुत कम मात्रा में पेयजल बचा हुआ है। दूसरे महानगरों का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। बंगलुरु का भूजल स्तर पिछले दो दशक में 10-12 मीटर से गिर कर 76-91 मीटर तक जा पहुंचा है। दिल्ली का भूजल भी लगातार कम हो रहा है। महाराष्ट्र 47 साल का सबसे बड़ा सूखा झेल रहा है। अन्य कई राज्य भी इसकी चपेट में आ गए हैं। नीति आयोग की मानें तो अभी जो रुझान हैं उनके जारी रहते 2020 तक 21 शहरों में भूजल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आयोग का कहना है कि 2030 तक देश की 40 फीसद आबादी इस गंभीर समस्या की चपेट में होगी। इस समस्या का एक सिरा सरकार से जुड़ता है तो दूसरा आम जनता से। जल प्रबंधन राज्यों का विषय है। अलग-अलग राज्यों में इसे लेकर अनेक नियम बने हुए हैं लेकिन उनका पालन कड़ाई से नहीं होता। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जल संरक्षण के लिए बनी कई सरकारी परियोजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। लोग अब भी पानी को लेकर लापरवाह रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पानी बचाने की सारी कवायद तीखी गर्मियों में ही होती है। बरसात शुरू होते ही तमाम प्रयास ढीले हो जाते हैं, जबकि पानी संचित करने की संभावना इसी सीजन में सबसे ज्यादा होती है। पानी को लेकर पारंपरिक रास्ते अपनाने और जल आंदोलन चलाने की बात सामाजिक कार्यकर्ता और विशेषज्ञ पहले से कहते आ रहे हैं पर अभी स्वयं प्रधानमंत्री ने इसे कहा है तो शायद सचमुच कुछ बदलाव देखने को मिले।